भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3066

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान की प्रगति

3066. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम संबंधी समाधानों पर विचार-विमर्श करने और पोषण अभियान की प्रगति का पता लगाने के लिए सभी राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी संयुक्त बैठकें हुई हैं और यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि देश में कोई भी महिला और बच्चे कुपोषित न रहें;

(ग) क्या सरकार शोलापुर सहित महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की संख्या के संबंध में आंकड़े रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौतियों के समाधान के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) में सम्मलित कर लिया गया है ।

मिशन पोषण 2.0 के तहत कुपोषण में कमी लाने और सामुदायिक भागीदारी, पहुंच, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी के माध्यम से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। यह योजना दुबलापन, अल्पवज़न की व्यापकता, ठिगनापन और एनीमिया को कम करने के लिए आयुष प्रथाओं के माध्यम से मातृ पोषण, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करती है।

मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकित सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्व-चयनित (कोई प्रवेश बाधा नहीं) योजना है और इसे देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भौतिक बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर नियमित आधार पर मिशन पोषण 2.0 सहित मंत्रालय की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री नियमित क्षेत्र दौरों के अलावा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती हैं। वर्ष 2022 में, मंत्रालय ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए 8 क्षेत्रीय बैठकें और 8 उप-क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की महिला एवं बाल विकास मंत्रियों ने भाग लिया था। वर्ष 2023 में, मंत्रालय ने भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की।

(ग) और (घ): शोलापुर सहित महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक-I

"पोषण अभियान की प्रगति" के संबंध में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा दिनांक 09.08.2024 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3066 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर में जून 2024 तक सोलापुर जिले सहित महाराष्ट्र राज्य में कुपोषित बच्चों का विवरण इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ठिगनापन % (0-6 वर्ष)**	**अल्पवज़न % (0-6 वर्ष)**	**दुबलापन % (0-5 वर्ष)**
महाराष्ट्र	42.5	17.8	4.8
सोलापुर जिला	41.2	11.5	3.3